दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 29 मार्च 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 178

महत्वपूर्ण एवं खास

केन्द्र ने बंगाल को भेजी 10 हजार कोरोनो वायरस परीक्षण किट

कोलकाता (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोरोनावायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए 10,000 परीक्षण किट भेजे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से किट भेज दी गई थीं। शुक्रवार को ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटरिक डिसीज (एनआईसीईडी) की वायरोलॉजी लैब में पहुंची। एनआईसीईडी के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में विभिन्न कोरोनावायरस परीक्षण प्रयोगशालाओं में किट भेजने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में परीक्षण किट की कमी की शिकायत की है। कुछ डॉक्टरों ने हाल ही में राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अपील की थी कि वे जल्दी किट भेजें।

पूरे परिवार को मारकर की खुदकुशी

पानीपत (आरएनएस)। हरियाणा के पानीपत शहर में एक 36 वर्षीय किराना विक्रेता ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मारने के बाद खुद को गोली मार ली। पुलिस ने बताया कि मृतक ने परिवार को और खुद को मारने के लिए अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया। मृतकों में उनकी आठ साल की बेटी और पांच साल का बेटा शामिल है। यह घटना राज नगर इलाके में हुई। पुलिस को संदेह है कि इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद कारण था।

गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों से मिलने पहुंचे सिसोदिया

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे लोगों से अपील है कि जहां हैं, वहीं रहे। आपको बताते जाए कि हजारों की संख्या में लोग उत्तरप्रदेश जाने के लिए इकट्ठे हो गए है। यूपी सरकार उनको ले जानें के लिए 1000 बसें लगा रहें हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर के पास पलायन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों के जाने के लिए कुछ डीटीसी बसें दी हैं, लोगों से अपील है कि जहां हैं, वहीं रहें। हमने गाजीपुर के स्कूलों में लोगों का ठहरने का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने घरों से ना निकलें। जिनके पास घर नहीं है, वो रैनबसेरे में रह सकता है।

दवाओं की होम डिलीवरी का आदेश

» कोरोना वायरस का असर

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोनोवायरस के प्रकोप के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 60 वर्ष से ऊपर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभार्थियों की दवाओं के होम डिलीवरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मधुमेह जैसी बीमारी या अन्य उपचार से गुजरने वाले लोग कल्याण केंद्रों का दौरा नहीं करेंगे। अपने आदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये (पुरानी बीमारियों के मामले में) तीन महीने के लिए एक बार में ही दवाएं दी जाएंगी। इसमें कहा गया है कि 60 या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग लाभार्थी, अंग प्रत्यारोपण, कीमोथेरेपी इत्यादि जैसे उपचार से गुजरने वाले लाभार्थी या घर पर रहने वाले किसी अन्य बीमारी से पीड़ित लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और अन्य केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के कर्मचारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा।

सीमा सड़क संगठन के जवान पुल बनाने, बर्फ हटाने के कार्य में जुटे

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 के खतरे का बहादुरी से सामना करते हुए, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के जवान दापोरिजो पुल (430 फुट मल्टी स्पैन बैली पुल) को बदलने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, जो अरूणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के सभी 451 गांवों में संचार लाइनों को बहाल करने और चीन सीमा पर स्थित सुरक्षा बलों की एकमात्र जीवन रेखा है।

घर वापसी के लिए दिल्ली-गाजियाबाद रोड पर उमड़े विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर

» लॉकडाउन के बाद छिन गया रोजगार

नईदिल्ली (आरएनएस)। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से दिल्ली में अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों में एक किस्म की बेचैनी और डर का भाव साफ देखा जा सकता है।

आवागमन के साधन बंद होने से इनकी चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसे केंद्र सरकार समेत दिल्ली और यूपी की सरकार के तमाम आश्वासन भी कम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि लोग पैदल ही सैकड़ों दूर अपने-अपने घरों की ओर निकल लिए हैं। हालांकि अब उन्हें बसें मुहैया कराने का काम शुरू हो गया है। शनिवार सुबह इसी बात की सूचना मिलते ही गाजीपुर और एनएच-24 पर हजारों की संख्या में भीड़ अल सुबह से मौजूद थी।

दिल्ली, गाजियाबाद में भी प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एनएच-24 पर तो कुछ मजदूरों की जमात पैदल घरों की ओर कूच करते देखी गई। वे लॉकडाउन के बाद आवागमन के साधन बंद होने से लोग पैदल जाने को मजबूर हैं और अचानक रोजगार छिन जाने के बाद मजदूरों के पास घर वापसी के सिवा चारा नहीं बचा है। एक लिहाज से देखें तो लॉकडाउन के कारण अचानक रोजगार छिन जाने के बाद मजदूरों के पास घर वापसी के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर से लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने के लिए बस चलाई जा रही हैं। बसों को देख लोगों में बस के अंदर घुसने को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है।

प्रशासन लगातार उन्हें आश्वस्त कर रहा है कि संयम रखें और बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। सुबह से बड़ी तादाद में लोग यहां मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बस लगाई जा रही हैं। हर बस में भी किसी तरह घुसने की कोशिश कर रहे लोगों में धक्का-मुक्की जारी है। लोगों की हुजूम मौजूद है।

राज्य में 1760 हुए कोरोना पीड़ित, 9 मिले पॉजिटिव

पटना (आरएनएस)। बिहार में शुक्रवार की सुबह दो मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई. हालांकि इसके बाद एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन संदिग्धों की सूची में शुक्रवार को 304 नए लोग शामिल किए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संदिग्धों की संख्या 1760 हो गई. बता दें कि गुरुवार तक 1456 लोग सर्विलांस में लिए गए थे।

पटना के अगमकुआं स्थित राजेंद्र मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. प्रदीप दास के अनुसार शुक्रवार को दो लोगों की अंतिम रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इनमें एक सिवान जिले का युवक है जो हाल ही में दुबई से लौटा था।

वहीं दूसरा संक्रमित युवक नालंदा जिले के नगरनौसा का निवासी है. वह उसी पटना के जगनपुरा स्थित सरनाम अस्पताल का कर्मचारी है जिसमें मुंगेर निवासी संक्रमित युवक भर्ती हुआ था। संक्रमित दोनों लोगों के गांवों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है. इन लोगों के संपर्क में आए सभी स्वजन के साथ अन्य लोगों को चारंटाइन कर उनके नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे।

वहीं बेगूसराय में गुरुवार की रात कोरोना के दो संदिग्ध की मौत के बाद दहशत है. बछवाड़ा थाना क्षेत्र की गोविंदपुर पंचायत के गांव में युवक और साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की सनहा पंचायत के गांव में वृद्धा की मौत हुई है। दोनों कुछ दिन पूर्व दूसरे राज्य से अपने गांव आए थे. दोनों के सैंपल पटना आरएमआरआइ भेजे गए हैं. दोनों के परिवार के एक दर्जन से ज्यादा लोगों को होम चारंटाइन किया गया है।

आपात स्थितियों में पीएम केयर्स फंड' में उदारतापूर्वक दान करने की अपील

नईदिल्ली (आरएनएस)। 'कोविड-19' की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके साथ ही विश्व भर में करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस खतरनाक ढंग से फैलता जा रहा है और हमारे देश के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य एवं आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। इस आपातकाल के मद्देनजर सरकार को आवश्यक सहयोग देने के उद्देश्य से उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को स्वेच्छा से अनगिनत अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

संकट की स्थिति, चाहे प्राकृतिक हो या कोई और, में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं क्षमताओं को हुए भारी नुकसान में कमी/नियंत्रण करने, इत्यादि के लिए त्वरित और सामूहिक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अतः अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण/विस्तार के साथ-साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और सामुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण करना आवश्यक है। नई प्रौद्योगिकी और अग्रिम अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग भी इस तरह के ठोस कदमों का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाता है।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से एक विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)' के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री शामिल हैं।

देश में पीड़ितों की संख्या पहुंची 900 के करीब

» महाराष्ट्र में मिले कोरोना के छह नए पीड़ित

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के 24 घंटे से भी कम समय में 110 नए मामले सामने आने के कारण देश में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 873 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार आज तड़के तीन तक देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 748 थी। इसके अलावा 66 लोग ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हो चुकी है। एक विदेशी उपचार के बाद देश से बाहर जा चुका है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के छह नए मरीज मिले हैं।

कृषि मंडियों,खरीद एजेंसियों, खेती की मशीनों, कृषि श्रमिकों को छूट

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र ने मंडियों, खरीद एजेंसियों, कृषि कार्यों, कृषि मशीनरी किराये पर लिये जाने वाले केंद्रों के साथ-साथ अंतर राज्यीय और राज्य के भीतर कृषि उपकरणों को लाने ले जाने जैसे कार्यों को कोरोना वायार संक्रमण के मद्देजन आवागमन की पाबंदी से छूट दी है। आने वाले कुछ दिनों में किसानों को रबी फसलों की कटाई में समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए यह फैसला किया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किए गए। इनके अनुसार सरकार ने कृषि श्रमिकों, साथ ही उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की विनिर्माण एवं पैकबंद करने वाली इकाइयों को भी लॉकडाउन ऑर्डर से मुक्त कर दिया है। इसमें कहा गया है कि

कृषि यंत्रों और खेती के कामकाज वाली मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी लॉकडाउन अवधि के दौरान काम करने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के कार्यकारिणी सदस्य देवव्रत शर्मा ने कहा कि मधुमक्खीपालक किसानों को भी शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की कॉलोनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट दी गई है जिसकी मांग हमने सरकार से की थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले बागवानी आयुक्त और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ बी एन एस मूर्ति ने सारे राज्यों के उद्यान निदेशकों को शहद निकालने और पर परागण के कार्य के लिए मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए छूट देने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ने अभी तक अनुमति दे दी है। बयान में कहा गया है,कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालन, एपीएमसी द्वारा संचालित मंडियों या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मंडी सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियों को छूट दी गई है।

रेल यात्रियों की टिकटों का वापस मिलेगा पूरा पैसा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण 21 मार्च से 14 अप्रैल की अवधि में बुक कराए गये टिकट रद्द माना जाएगा और रेलवे उन्हें टिकटों की पूरी राशि वापस करेगा।

रेल मंत्रालय के मुताबिक 14 अप्रैल तक सभी यात्री ट्रेनों और सभी यात्री टिकटों को रद्द करने के मद्देनजर भारतीय रेलवे द्वारा 21 मार्च से 14 अप्रैल तक यात्रा की अवधि के लिए सभी टिकटों के लिए पूर्ण रिफंड देने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने अनुदान की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा गया है कि काउंटर बुक पीआरएस टिकट के लिए 27 मार्च से पहले रद्द किए गए टिकटों की टिकट जमा रसीद यात्री को यात्रा विवरण के साथ किसी भी जोनल रेलवे के मुख्य

» भारतीय रेलवे ने जारी किये आदेश

वाणिज्यिक प्रबंधक (दावों) या मुख्य दावा अधिकारी के लिए एक फार्म भरकर दाखिल करना होगा। बैलेंस रिफंड राशि का लाभ उठाने के लिए 21 जून 2020 तक की अवधि। रेलवे एक उपयोगिता प्रदान करेगा जिसके माध्यम से यात्री ऐसी टिकटों को रद्द करने के दौरान कटौती की गई राशि की वापसी का लाभ उठा सकता है।ज बकि 27 मार्च के बाद रद्द किए गए टिकटों के लिए भी सभी निरस्तीकरण के संबंध में पूर्ण वापसी देय होगी। इसी प्रकार रेलवे के मुताबिक जो ई-टिकट 27 मार्च से पहले रद्द किए गए हैं उनके बैलेंस रिफंड राशि को उस यात्री के खाते में जमा किया जाएगा, जहां से टिकट बुक किया गया था। आईआरसीटीसी बैलेंस रिफंड राशि प्रदान करने के लिए एक उपयोगिता तैयार करेगा। जबकि 27 मार्च के बाद रद्द किए गए ई–टिकट के सभी निरस्तीकरणों के संबंध में पूर्ण वापसी देय होगी, जिसके लिए पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं। आवश्यक सामानों की आपूर्ति जारी भारतीय रेलवे पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के साथ जारी है। कल 34000 से अधिक फ्रेट वैगन लोड किए गए थे।

कोयला आपूर्ति के रखरखाव को सुनिश्चित करने कार्य कर रहा है मंत्रालयः जोशी

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय कोयला, खनन और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सुनिश्चित करते हुए कहा कि कोयला आपूर्ति को एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है तथा कोयला मंत्रालय के सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान कोयले की आपूर्ति बनी रहे, ताकि वर्तमान परिस्थिति में बिजली और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र

अप्रभावित रहें। मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की कोयला उत्पादन, आपूर्ति और प्रेषण की निगरानी के लिए प्रतिदिन बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 मार्च 2020 को पहली ऐसी बैठक ली। प्रतिदिन कोयला मंत्री को रिपोर्ट भी दी जाएगी। चूंकि कोयला मंत्रालय पूरी तरह से कागज-रहित कार्यालय है, सभी कर्मचारी मंत्रालय के ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर या घर से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

रेलवे ने अपने कर्मचारियों से मांगा एक दिन का वेतन

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेल बोर्ड ने अपने कर्मचारियों से प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी एक दिन की सैलरी दान देने की अपील की है। उसने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के प्रयासों को समर्थन देने के लिए सभी से मदद करने के लिए कहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी जनरल मैनेजर क उनसे अपने-अपने जोन के कर्मचारियों से दान के लिए अपील करने को कहा है। बोर्ड ने अपने पत्र में कहा, रेलवे के हर एक कर्मचारी से अपील की जानी चाहिए कि वह कम से कम एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर अपना योगदान दे। बोर्ड ने यह भी कहा कि कोरोनो वायरस देश की सबसे खराब और सबसे अभूतपूर्व आपदा है। इसके खिलाफ जंग में सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए और जो भी स्वेच्छा से दान देना चाहे उनसे एक दिन का वेतन लेना चाहिए।

» राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया

लॉकडाउन दौरान प्रवासी कामगारों को सहायता उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध है सरकारः शाह

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार, सरकार लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी कामगारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है।

यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही। प्रवासी कामगारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मोदी सरकार की अभिलाषा के साथ केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को फिर से पत्र लिखकर लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने गृह राज्यों को लौट रहे या ऐसा करने का प्रयास कर रहे प्रवासी कामगारों/तीर्थयात्रियों आदि के लिए तत्काल राहत शिविर स्थापित करने का अनुरोध किया

है। राज्यों को लाउड स्पीकर्स, प्रौद्योगिकी और स्वयंसेवियों तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सेवाओं का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के बारे में सटीक सूचना को व्यापक रूप से प्रचारित करने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने का परामर्श दिया गया है। राज्यों को राजमार्गों से गुजर रहे लोगों के लिए उनसे सटे क्षेत्रों में राहत शिविर लगाने, साथ ही लॉकडाउन का आदेश जारी रहने तक इन लोगों का राहत शिविरों में रहना सुनिश्चित करने के लिए तम्बू लगाने की भी सलाह दी गई है। उन्हें परामर्श दिया गया है कि इन आश्रय स्थलों को तैयार करते समय सामाजिक दूरी सहित विविध सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तीन करोड़ बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को तीन माह का पेंशन एडवांस

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए करीब तीन करोड़ विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को अप्रैल के पहले हफ्ते में तीन माह का पेंशन एडवांस देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इन्हें अग्रिम पेंशन सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। 60-79 साल वाले बुजुर्गों को अभी 200 रुपये प्रति माह, जबकि 80 साल या उससे ऊपर उम्र वाले बुजुर्गों को हर माह 500 रुपये मिलते हैं।